



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 760) पटना, मंगलवार, 29 अगस्त 2017

सं0 3ए-2-वे०पु०-09/2016-5978/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

25 अगस्त 2017

विषय:—माह फरवरी से जून, 2006 के बीच देय वार्षिक वेतन वृद्धि वाले राज्यकर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप दिनांक 01/01/2006 को अपनरीक्षित वेतनमान में एकबारीय एक वेतन वृद्धि के लाभ के सम्बन्ध में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा स्वीकृत करने के संबंध में।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं०-10/2/2011-ई.III/ए दिनांक 19/03/2012 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि “केन्द्र सरकार ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें वर्ष 2006 में फरवरी से जून के बीच अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होनी थी, उन्हें एकबारीय उपाय के तौर पर पूर्व संशोधित वेतनमान में 01/01/2006 को एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाय और तत्पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली (संशोधित वेतन)-2008 के नियम-10 के अनुसार, संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01/07/2006 को मिलेगी”।

उल्लेखनीय है कि वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-10 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी राज्य कर्मियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई को निश्चित की गई है। इस हेतु यह शर्त भी निर्धारित है कि पहली जुलाई को संशोधित वेतन संरचना में न्यूनतम छः माह की सेवा अवधि पूरा करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि पाने के हकदार होंगे। ऐसी स्थिति में माह फरवरी से जून, 2006 के बीच देय वार्षिक वृद्धि वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01/07/2006 को वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया गया।

2. उक्त क्रम में राज्य कर्मियों द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमान्य किये जाने की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए वित्त विभाग द्वारा मामले को सातवें राज्य वेतन आयोग को refer करने का निर्णय लिया गया।

3. राज्य वेतन आयोग ने उक्त मामले के संदर्भ में अपनी अनुशंसा पत्रांक-474, दिनांक 27/06/2017 द्वारा राज्य सरकार को सौंप दी है। आयोग की अनुशंसा का सार निम्नवत् है:-

"This Commission, too, feels that old matters be not re-opened unless they be the cause of extreme hardship. That being be not the case, and also because accepting the said amendment would be a difficult exercise in terms of administrative effort, this commission recommends that the said Amendment not be given effect to with respect to State Employees."

4. सातवें राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि माह फरवरी से जून, 2006 के बीच देय वार्षिक वेतन वृद्धि वाले राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप दिनांक 01/01/2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एकबारीय एक वेतन वृद्धि के लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 760-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>